मोदी सरकार की कोई दुस्साहसिक कार्रवाई अलगाववादियों की मदद ही करेगी

जनचौक ब्यूरो

नई दिल्ली। पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों के परिवारों के दु:ख के साथ हम पूरी तौर पर शरीक हैं और अपनी एकजुटता सेना और सुरक्षा दलों के साथ व्यक्त करते हैं। पुलवामा की घटना भारी सुरक्षा चूक और मुख्य तौर पर मोदी सरकार की लगभग पिछले 5 वर्षों से चल रही कश्मीर नीति व पाकिस्तान नीति की असफलता का परिणाम है और मोदी सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

यह बातें आज ओबरा कार्यालय में सोनभद्र, मिर्जापुर व चंदौली के अगुवा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हुए स्वराज अभियान के राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य अखिलेंद्र प्रताप सिंह ने कहीं।

उन्होंने कहा कि भाजपा कश्मीर समस्या को हल करने में कम और कश्मीर घाटी में अपना जनाधार ब ?ने में ज्यादा दिलचस्पी ले रही थी। इसी के तहत जिस पीडीपी के बारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा आतंकियों के सहयोगी दल होने की बात करते थे उसके साथ उन्होंने मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई और पार्टी स्वार्थ में ही सरकार को भी गिरा दिया। घाटी में शांति बहाली और लोगों के अलगाव को दूर करने की कोई राजनीतिक समझ मोदी सरकार में नहीं दिखी। उनके कार्यकाल में केंद्र सरकार व राज्य सरकार से कश्मीरी अवाम का अलगाव बढ़ता गया और आज हालत यह हो गई कि कश्मीरी नौजवान आत्मघाती दस्ते में तब्दील होते जा रहे हैं।

पूरे देश को अपने रंग में रंगने की आरएसएस की जो आत्मघाती व वैचारिक कट्टरपन की नीति है, उसी का परिणाम है कि उत्तर पूर्व में भी अलगाव बढ़ रहा है और नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में उत्तर पूर्व भारत में 'हैलो चाईना बॉय बॉय इंडिया' के नारे लग रहे हैं। कश्मीर की समस्या इजराइल के विरूद्ध फिलीस्तीन के पैटर्न पर बढ़ती जा रही है जो पूरी तौर पर चिंताजनक है। पाकिस्तान के बारे में भी कोई ठोस नीति मोदी सरकार की नहीं दिखती है। कभी दोस्ती कभी युद्ध का माहौल बनाया जाता है।

दरअसल पूरी विदेश नीति ही दिशाहीन हो गई है और सभी पड़ोसी मुल्कों के साथ संबंध खराब होते गए हैं। यहां तक कि भूटान से भी पहले वाले सहज सम्बंध नहीं रह गया है। इस पृष्ठभूमि में पाकिस्तान के विरूद्ध लिया गया कोई भी दुस्साहसिक कदम अलगाववादियों का मनोबल बढ़ाएगा, कश्मीर की समस्या को और जटिल करेगा और विदेशी ताकतों को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का मौका देगा। इराक और अफगानिस्तान में अमरीकी दमन के बावजूद आतंकी घटनाएं खत्म नहीं हुई हैं।

भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके संगठनों द्वारा पैदा किया जा रहा युद्धोन्माद व सांप्रदायिकता चिंताजनक है, इससे देश को बचने की जरूरत है। जो लोग 'खून का बदला खून', 'युद्ध करो-युद्ध करो' का नारा लगा रहे हैं वह लोग बेरोजगारी, दरिद्रता व भयावह गरीबी में फंसे आम जनजीवन की जिंदगी को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हैं और युद्ध से मालामाल होने वाले हथियार के सौदागरों को मदद पहुंचा रहे हैं। 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध इन्दिरा की जीत की नसीहत का आज कोई मायने मतलब नहीं है, क्योंकि उस समय उनकी जीत के पीछे अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के संतुलन के साथ-साथ बंगलादेश की मुक्ति का राष्ट्रीय आंदोलन भी था। इसलिए ऐसे नाजुक वक्त में देश को नफरत व उन्माद में धकेलने की जगह ठण्डे दिमाग से प्रभावशाली राजनैतिक-कूटनीतिक पहल लेने की जरूरत है।

जिससे पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सके और कश्मीर की आवाम का विश्वास भी जीता जा सके। हमें यह याद रखना होगा कि राजनीतिक खालीपन में ही अलगाव और आतंकी घटनाएं ब ?ती हैं। इसलिए हिंसा और युद्धोन्माद नहीं कश्मीर के सभी हिस्सेदारों (स्टेक होल्डरों) से वार्ता की जरूरत अब भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना चार साल पहले थी। इस तरह की कार्यवाही यदि चार साल पहले हुई होती तो सम्भवत: उरी, पठानकोट और अब पुलवामा जैसी आतंकी घटनाओं से देश बच गया होता और किसानों, मजदूरों और गरीबों के सैनिक बेटों की जिदंगी बच गयी होती।

पति, पत्नी की मौत पर परिवार को नहीं मिलेगा पेंशन फंड का पैसा

एक तरफ देश के हिंदुओं को पुलवामा हमले के नाम पर कश्मीरी और अन्य मुसलमानों के विरुद्ध भड़काकर चुनावी खेल खेला जा रहा है,दूसरी तरफ इसकी आड़ में सरकार कई जनविरोधी फैसले ले रही है।लोग जब भड़के हुए हों तो पूँजीपतियों के पक्ष में और गरीबों के विरुद्ध फैसले लेना आसान हो जाता है।

अभी- अभी सरकार ने स्टील अथारिटी आफ इंडिया(सेल)की तीन इकाइयों को निजी क्षेत्र के हवाले करने का फैसला किया है। एक महीने पहले वह एयर इंडिया समेत तीस सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण का फैसला कर चुकी है। जिस अनिल अंबानी को उपकृत करने के लिए मोदी जी ने सरकारी कंपनी एच ए एल को बर्बाद किया,उस अंबानी का हाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद वह 453 करोड़ रुपये तय समय पर स्वीडिश कंपनी एरिक्सन को दे नहीं पाया। जो जेल की हवा खाने के कगार पर आ चुका है,वह राफेल बनाएगा।हँसना या रोना मत बिल्कुल!

उधर अनिल अंबानी के बड़े भाई मुकेश अंबानी को उपकृत करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को नये तेल क्षेत्र की तलाश करने पर तेल की कीमत तय करने की 'स्वतंत्रता' दी गई है। यह स्वतंत्रता ओएनजीसी के साथ उसे दी गई है मगर चुनाव के समय दिखावे के लिए,ताकि नया राफेल पैदा न हो।

और इस सबके साथ घरेलू काम करनेवाले, रेहड़ी-पटरीवालों,मोचियों, रिक्शा चालकों, भवन निर्माण मजदूरों की मेहनत की कमाई छीनने की तैयारी है। उनके लिए चलाई गई श्रमयोगी मानधन योजना,जो 60 साल की उम्र पार चुके गरीबों को तीन हजार रुपये पेंशन देने के नाम पर घोषित की गई है, उसमें यह व्यवस्था की गई है कि अगर इस योजना में शामिल पति- पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो उनके अनाथ बच्चों को पेंशन तो नहीं ही मिलेगी बल्कि इस योजना के लिए उन गरीबों ने जो पैसा हर महीने दिया है,उसे भी सरकार हड़प लेगी। अभी हिंदू- मुसलमान और होगा और पूँजीपतियों की खुली लूट और चलेगी। पूँजीपति सारा फायदा सांप्रदायिकता की आड़ में बटोर लेना चाहते हैं।क्या पता कल मोदी जी कुर्सी पर हों न हों!

तो यह असली राज है कश्मीरियों, मुसलमानों के विरुद्ध भड़काने का और पाकिस्तान से युद्ध का माहौल बनाने का और.खुदा न खास्ता मोदी जी जीत गए तो हम सबकी टैक्सों और दमन से वाट लगा देंगे। जय मोदी,जय हिंदुत्व।

- साइबर नजर

पुलवामा हमले के बाद कश्मीर के असली मुद्दे को फिर नज़रअंदाज़ किया जा रहा है

आलोक अस्थाना

आखिर क्यों स्थानीय कश्मीरी, जो अपेक्षाकृत रूप से पढ़े-लिखे और संपन्न हैं, इस तरह अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं?

पुलवामा में 14 फरवरी को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के काफिले पर फिदायीन हमले ने एक बार फिर भारत को इस बात का एहसास कराया है कि पिछले एक साल में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बल की कामयाबियों का मतलब यह नहीं है कि जम्मू और कश्मीर में सब कुछ सही है.

लेकिन इस हमले के बाद टीवी और दूसरे माध्यमों में होनेवाली बहसों के भटकाव इस ओर इशारा करते हैं कि हम अभी भी समस्याओं की ओर सही तरीके से नहीं देख रहे हैं. फिलहाल हम एक अकादमिक बहस से रूबरू हैं, जिसमें विशेषज्ञ अपनी बात को मजबूती से रखने की कोशिश करते हैं- लेकिन इससे देश को कोई भी मदद नहीं मिलनेवाली.

विशेषज्ञों द्वारा जिन मसलों पर जोर दिया जा रहा हैं, उनमें से कुछ इस तरह हैं

जैश-ए-मोहम्मद के मसूद अजहर और उसका बचाव करने में चीन की भूमिका

इस्तेमाल किए गए विस्फोटक की चिंताजनक मात्रा- जो कथित तौर पर 350 किलोग्राम था.

आतंकवादियों को कथित तौर पर बढ़ावा देने में जम्मू और कश्मीर के राजनीतिक दलों की भूमिका.

जम्मू से श्रीनगर तक जमीन के रास्ते से जवानों के परिवहन में अनिवार्य रूप से शामिल जोखिम और हवाई रास्ते से सैनिकों का परिवहन करने की जरूरत.

वह भू-रणनीतिक (Geo-strategic) हालात, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकलनेवाला है, जबकि भारत में आम चुनाव होनेवाले हैं.

सैनिकों की ट्रेनिंग या ट्रेनिंग का अभाव, जिसका नतीजा कमजोर आरओपी (रोड ओपनिंग पार्टी) ड्यूटी के तौर पर निकला.

मेरा मानना है कि अहमद के आत्मघाती विस्फोट से हुए खून-खराबे से सामने आया मुख्य सवाल यह है: आखिर स्थानीय कश्मीरी, जिनमें से कई अपेक्षाकृत संपन्न और शिक्षित हैं, इस तरह से अपनी जान देने के लिए क्यों तैयार हैं?

आतंकवादियों द्वारा नई रणनीति के तहत विस्फोटक से भरे वाहन का इस्तेमाल.

इसमें कोई शक नहीं ये सब वाजिब चिंताएं हैं, लेकिन ये इस कहावत को पुख्ता करती हैं कि जब आपके पास केवल एक नजरिया होता है, तब आप हर समस्या को उसी चश्मे से देखते हैं. विशेषज्ञों की आदत किसी समस्या को अपनी विशेषज्ञता के संदर्भ में देखने की होती है.

असली सवाल यह है कि आखिर वह एक मसला क्या है, जिसका समाधान करने से सबसे बेहतर नतीजे हासिल होंगे?

गुरुवार का हमलावर पुलवामा का आदिल अहमद था. वह पाकिस्तानी नहीं था, न ही वह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आया था.

मेरा मानना है कि अहमद के आत्मघाती विस्फोट से हुए खून-खराबे से सामने आया मुख्य सवाल यह है- आखिर स्थानीय कश्मीरी, जिनमें से कई अपेक्षाकृत संपन्न और शिक्षित हैं, इस तरह से अपनी जान देने के लिए क्यों तैयार हैं?

अगर इस सवाल का थोड़ी ही सही, जवाब दे दिया जाता है, तो बाकी सारी चीजों का भी समाधान निकल जाएगा. मैंने एक भी विशेषज्ञ को, जिनमें जम्मू और कश्मीर के सियासतदान भी शामिल हैं, इस मूल मसले पर बात करते हुए नहीं सुना है.

हो सकता है कि उनमें यह डर हो कि इस समय जन-भावनाएं इस तरह की हैं कि जो कोई भी इस रास्ते पर चलेगा, वह सहानुभूति और उससे भी बढ़कर वोट गंवा बैठेगा.

भारत ने पहले ही पाकिस्तान के मोस्ट फेवर्ड नेशन के कारोबारी दर्जे को रद्द कर दिया है. जिस समय मैं यह लिख रहा हूं, प्रधानमंत्री को टीवी पर कहते हुए सुन रहा हूं, 'जनता का खून खौल रहा है. यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा. हम सभी को राजनीति से ऊपर उठना चाहिए.'

यहां कौन-सी राजनीति है? यह मूल मसले से या एक केंद्रीय हल की तरफ से आंखें मूंदना है क्योंकि उनके बारे में बात करने से सार्वजनिक समर्थन या वोटों का नुकसान होने की संभावना है.

राहुल गांधी ने पहले ही विपक्ष के सरकार के साथ खड़े होने की बात कह कर रक्षात्मक रुख अख्तियार कर लिया है. कोई भी जोखिम मोल नहीं ले रहा है. लेकिन इसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है.

ज्यादा वोट की इच्छा के सामने देश पीछे छूट गया है. ऐसा लगातार हो रहा है- लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, जब हमारे पास इसका सामना करने के अलावा कोई और चारा नहीं होगा.

तब तक हम दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बना सकते हैं, मानो इससे जम्मू-कश्मीर में कश्मीरियों- जो भी भारत के नागरिक हैं, की कुछ शिकायतों का निपटारा हो जाएगा.

उन्हें इस बात से जरूर परेशानी हो रही होगी कि उनकी सरकार देश के दूसरे नागरिकों को संतुष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, भले ही इसके लिए उसे कर्जमाफी करनी पड़ी, जिसका बोझ उठाने की क्षमता अर्थव्यवस्था में नहीं है या नौकरी में आरक्षण का ऐसा प्रावधान करना पड़े, जिसे संविधान और सुप्रीम कोर्ट से मान्यता नहीं मिलेगी.

कश्मीरियों के लिए कुछ देने की बात करने के लिए भले ही यह माकूल समय न हो, लेकिन सवाल उठा है कि क्या ऐसा समय कभी आएगा भी? निश्चय ही इस समस्या के फिर से उभरने पर सही स्थितियां बनेंगी, जिनसे मूल मुद्दे का समाधान होगा.

शहीद रतन के परिवार से मिली भाकपा-माले टीम, झूठे और खोखले घोषणाओं में व्यस्त है सरकार

भागलपुर , पुलवामा में शहीद हुए जवानों में से एक रतन कुमार ठाकुर के शोक – संतप्त परिवार से 20 फरवरी को भाकपा-माले की एक टीम ने उनके गांव मदारगंज, रतनपुर (भागलपुर जिला का सन्हौला प्रखंड) में जाकर मुलाकात की और शोक संवेदना जाहिर करते हुए परिवार के इस अवर्णनीय दुख में भागीदार हुए । टीम में शामिल माले नेताओं-कार्यकर्ताओं ने शहीद के परिवार व ग्राम वासियों के साथ मिलकर शहीद रतन कुमार ठाकुर की तस्वीर पर माल्यार्पण व दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी ।

टीम में भाकपा-माले के राज्य कमिटी सदस्य एस. के. शर्मा, नगर प्रभारी व ऐक्टू के राज्य सचिव मुकेश मुक्त, जिला सचिव बिंदेश्वरी मंडल, जिला कमिटी सदस्य व अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला उपाध्यक्ष रणधीर यादव, स्थानीय माले नेता विजय यादव, बादल तांती व राजू मंडल शामिल थे ।

टीम ने बताया कि शहीद रतन कुमार ठाकुर अपने पीछे पत्नी – राजनंदनी देवी, पुत्र – कृष्णा कुमार (3 वर्ष), पिता– राम निरंजन ठाकुर, छोटा भाई – मिलन कुमार, छोटी बहन –नीतू कुमारी ज्कुल 5 सदस्य छोड़ गए है । सभी शहीद रतन कुमार ठाकुर पर ही आश्रित थे । गर्भवती पत्नी गहरे सदमे में है, पुरे परिवार का हाल बुरा है । इस गहरे आघात में पूरा गांव शहीद परिवार के साथ खड़ा है । पूरे देश में जहां एक तरफ जवानों के शहादत के बहाने माहौल बिगाड़ने के लिए साम्प्रदायिक– फासीवादी ताकतें सक्रिय है वहीं शहीद के गांव में गहरी साम्प्रदायिक सद्भावना दिखी । गांव पहुंचते ही टीम की अगुवानी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने किया । ग्रामीण युवा मो. मंजूर ने आगे बढ़कर टीम का स्वागत किया और शहीद के घर ले जाकर बैठने की व्यवस्था की ।

टीम ने बताया कि सरकार सिर्फ झूठी और खोखले में घोषणाओं में व्यस्त है । शहादत के 6 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक सरकार की ओर से शहीद परिवार को कुछ नहीं मिला, कोई सहायता नही मिली है । शहीद के पिता ने बताया कि दाह संस्कार के बाद कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी सुध लेने नही आया । फोन करने पर स्थानीय डॉक्टर पुष्पलता देवी बहु को देखने अवश्य आ जाते है CRPF के दो जवान घर पर मजूद है । शहीद के पिता एवं ग्रामीण दिवाकर सिंह ने सवाल करते हुए कहा कि आतंकी पाकिस्तान से तो आए नहीं थे ? ज्सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई । सुरक्षा व्यवस्था ठीक रहता तो शहादत नही होती ! आतंकी हमले का शिकार हमेशा गरीब का बेटा ही क्यों होता है ज्बड़े और पैसे वाले घरों से तो सेना में लोग जाते नही ! आखिर कब तक गरीब के बेटों की कुर्बानी दी जाती रहेगी ?

कमलाकांत ठाकुर (शहीद के ससुर) ने कहा कि अभी हमारे बेटों की शहादत के बहाने हंगामा किया जा रहा है ज्पूरी जिंदगी तो इस आघात को अकेले ही झेलना है । सत्ता के खेल में हमारे बेटों की कुर्बानी इस देश की नियति बन गई है । मौत का व्यापार बंद होना चाहिए । नफरत फैलाकर आतंकवाद को बढ़ाने के बजाय इसे खत्म करने के बारे में सोचा जाना चाहिए ।

टीम ने अर्पण ठाकुर, राहुल कुमार, किशन ठाकुर, सोएब आलम, सुशील कुमार, बिहारी सिंह, राघवेंद्र ठाकुर आदि दर्जनों ग्रामीणों से भी मुलाकात की । ग्रामीणों ने बताया कि बरसात में गांव की टूटी, जर्जर सड़के घुटने भर पानी में डूबा रहता है । चलना मुश्किल हो जाता है । पानी निकासी का कोई साधन नही है और पेय जल की घोर कमी है, इसका इंतजाम करने के लिए प्रशासन ने कोई प्रयास भी नही किया कभी । नीतीश की सात निश्चय योजना शहीद के गांव में पूरी तरह फैल है।

भाकपा-माले ने मांग की कि–

– सरकार ने जो सहायता राशि घोषित की वह अविलम्ब शहीद परिवार को उपलब्ध कराया जाय ।

– शहीद के पत्नी और भाई को सरकारी नौकरी दिया जाय

– शहीद के गांव को आदर्श ग्राम बनाया जाय ।

इस गहरे आघात की घड़ी में भाकपा-माले शहीद परिवार के साथ खड़ा है और हर प्रकार के दुख में बराबर का भागीदार है ।